ग्रामीण-शहरी लिंकेज : चुनौतियां एवं अवसर

—डॉ. नेहा पालीवाल

भारत में ग्रामीण-शहरी लिंकेज को बढ़ाए जाने की कई संभावनाएं मौजूद हैं किन्तु इस मार्ग में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ग्रामीण-शहरी लिंकेज बढ़ाने हेतु आधारभूत संरचना व बाजार एवं गैर-बाज़ारगत संस्थाओं के विकास में स्थानीय सरकारों एवं निजी निवेश को बढ़ाने वाली नीतियों के निर्माण की आवश्यकता है। इस दिशा में किए जा रहे सरकारी प्रयासों के साथ यदि जनसहभागिता में भी वृद्धि हो तो ग्रामीण-शहरी लिंकेज भारत में न केवल समावेशी व सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा वरन् गरीबी हटाने व बेरोजगारी की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है तथा सरकार इसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में खड़ा करने के लिए दृढ़–संकल्पित है। हमारा यह स्वप्न तभी साकार होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण तथा शहरी विकास दोनों को समान महत्व दिया जाएगा। यहां तक कि एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र की सहायता से ही किया जाएगा।

विकास के जो मॉडल पूर्व में अपनाए गए वो अर्थव्यवस्था के ग्रामीण व शहरी विभाजन पर आधारित थे। किन्तु वर्तमान में यह तथ्य सर्वमान्य है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय रूप से अंतःनिर्भर हैं। अतः अर्थव्यवस्था के विकास में ग्रामीण–शहरी लिंकेज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह आलेख भारत में ग्रामीण–शहरी लिंकेज के महत्व एवं चुनौतियों के विश्लेषण के साथ समाधान सुझाता है। भारत में ग्रामीण–शहरी लिंकेज बढ़ाने हेतु किए गए सरकारी प्रयासों के साथ भारत में उपलब्ध नए अवसरों की भी व्याख्या करता है।

ग्रामीण–शहरी लिंकेज की अवधारणा एवं महत्व

ग्रामीण–शहरी लिंकेज से तात्पर्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की सम्बद्धता एवं अन्तर्निर्भरता से है जो वस्तुओं व व्यक्तियों के द्विपक्षीय प्रवाह द्वारा परिलक्षित होती हैं। एक ओर जहां ग्रामीण क्षेत्र से कृषि एवं अन्य उत्पादों को स्थानीय उपभोग या राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजने के उद्देश्य से शहरी बाजारों में प्रेषित किया जाता है वहीं दूसरी ओर शहरी केन्द्रों से निर्मित उत्पादों

का ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग या निवेश हेतु प्रवाह होता है। वस्तुओं के साथ–साथ व्यक्तियों का प्रवाह भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होता है। ग्रामीण क्षेत्र से व्यक्तियों का प्रवर्जन शहरी क्षेत्र की ओर रोजगार, शिक्षा व अन्य कारणों से होता है। वहीं शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तियों का प्रवाह स्थायी या अस्थायी रूप से निर्मित उत्पादों के विक्रय, निवेश या सामाजिक कारणों से होता है।

अन्य अल्प–विकसित राष्ट्रों के समान भारत में भी वर्तमान में तीव्र शहरीकरण की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। शहरों में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में जहां 2001 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 27.8 प्रतिशत था वह 2011 में बढ़कर 31.2 प्रतिशत हो गया है। यद्यपि बढ़ता शहरीकरण विकास का द्योतक है किन्तु यह ग्रामीण क्षेत्र के संसाधनों व श्रमबल के शोषण पर आधारित होता है। शहरी क्षेत्र पर आधारित विकास मॉडल ग्रामीण क्षेत्र को उद्योगों के लिए श्रमिकों व कच्चे माल के एक स्रोत के रूप में देखता है व इस क्षेत्र की इतनी ही उन्नति स्वीकार करता है जिससे श्रमिकों की पुनरोत्पत्ति होती रहे व इस क्षेत्र से गरीब व्यक्तियों का शहरी क्षेत्र में कार्य की तलाश में आना जारी रहे।

तीव्र एवं अनियोजित शहरीकरण से शहरी क्षेत्र में विकास बाधित होता है व ग्रामीण क्षेत्र से गरीबों की संख्या शहरी क्षेत्र में बढ़ने लगती है।

अतः अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण विकास के लिए ग्रामीण विकास की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कृषि क्षेत्र व उसका विकास प्रारम्भ से ही आर्थिक विकास की धुरी रहे हैं। भारत में भी प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास था। ग्रामीण व कृषि क्षेत्र के विकास से न केवल शहर के उद्योगों को कच्चा माल मिलता है वरन् कृषि आगतों, मशीनों, उर्वरकों आदि के निर्मित उत्पादों के लिए एक बाजार भी उपलब्ध होता है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास से प्राप्त आधिक्य पूंजी शहरी विकास में भी महती भूमिका निभाती है।

अतः औद्योगिकीकरण व शहरी विकास की नीति बिना ग्रामीण विकास के फलदायी नहीं हो सकती। जहां ग्रामीण क्षेत्र का विकास कृषि क्षेत्र के विकास पर निर्भर है, जो स्वयं शहरी उद्यमों व व्यवसायों के विकास पर निर्भर करता है वहीं शहरी क्षेत्र का सतत विकास भी ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि, सम्पन्नता एवं विकास पर निर्भर करता है। अतः अर्थव्यवस्था के सतत् एवं समावेशी विकास हेतु ग्रामीण–शहरी लिंकेज को बढ़ाने की महती आवश्यकता है।

विश्व बैंक (2006) के अनुसार ग्रामीण–शहरी लिंकेज की उपेक्षा अकुशलता की ओर ले जाती है व वृद्धिजनित असमानता का कारण होती है। वास्तव में कम आय वाले देशों में हुए औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण अंश कृषि क्षेत्र के साथ अग्रगामी एवं पश्चगामी लिंकेज का परिणाम है। ग्रामीण–शहरी लिंकेज के अवसरों व चुनौतियों की अच्छी समझ सही आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से सतत् विकास की ओर अग्रसित करती हैं।

भारत में ग्रामीण–शहरी लिंकेज की चुनौतियां एवं समाधान

भारत में ग्रामीण–शहरी लिंकेज की मुख्य चुनौतियां आधारभूत संरचना की कमी एवं बाजार व गैर–बाजारगत संस्थाओं की अकुशलता है।

ग्रामीण–शहरी लिंकेज के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों व वस्तुओं के द्विपक्षीय प्रवाह में मुख्य बाधा परिवहन सुविधाओं व संरचना की अपर्याप्तता है। आज भी भारत में कई गांव पक्की सड़कों के माध्यम से शहरों से नहीं जुड़े हैं। वर्ष 2011 में 61.29 प्रतिशत ग्रामीण सड़कें कच्ची थीं । मानसून के समय उनका सम्पर्क शहरों से टूट जाता है जिससे आपूर्ति न होने तथा भण्डारण की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण फल–सब्जी, दूध जैसी नाशवान वस्तुओं की भारी मात्रा खराब हो जाती है। दैनिक मजदूरी के लिए शहर जाने वाले श्रमिक परिवहन की अपर्याप्त सुविधाओं के

कारण हतोत्साहित होते हैं। जिन गांवों में पक्की सड़कें नहीं हैं वे शहरों के निकट होते हुए भी अलग–थलग पड़ जाते हैं। यहां तक कि वहां शहर का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी तक के लिए पदस्थापना नहीं चाहता। ऐसे गांवों के बच्चे शिक्षा अर्जन के लिए आगे नहीं जा सकते। अतः ग्रामीण–शहरी लिंकेज में परिवहन सुविधाओं का विकास एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना, भारत निर्माण योजना तथा प्रधानमंत्री सड़क योजना का पुनःआरम्भ इसी दिशा में एक सरकारी प्रयास है।

परिवहन के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र में संचार एवं बिजली की सुविधाओं का अभाव भी ग्रामीण–शहरी लिंकेज के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कम्प्यूटर व मोबाइल के इस युग में आज भी भारत के कई गांवों में टेलिफोन की सुविधा तो दूर डाक तक नहीं भेजी जा सकती है। भारत के 1,25,000 गांव आज भी बिजली से वंचित हैं। ऐसे में गांवों में उद्यम विकास की बातें करना बेमानी है। इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए सरकार प्रयासरत है। बिजली के महत्व को समझते हुए सरकार ने गांवों में प्रतिदिन 24 घंटे अबाधित बिजली उपलब्ध कराने हेतु दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लागू की है।

व्यापार ग्रामीण–शहरी लिंकेज को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण घटक है। किन्तु भारत में विपणन नीतियां व विपणन केन्द्रों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाया है। कृषि कीमत नीति व उसकी व्यवहार्यता संतोषप्रद नहीं है। कृषि उत्पादों की कीमतों में अधिक उच्चावचनों से कृषकों को फसलों के सही भावों की जानकारी हासिल नहीं हो पाती जिससे कृषि क्षेत्र का विकास हतोत्साहित होता है। इस हेतु कृषि कीमत स्थिरता व मण्डियों को अधिक कुशल बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। सरकार ने कृषि उत्पादों की स्थिरता हेतु 'कीमत स्थिरता कोष' स्थापित किया है।

ग्रामीण क्षेत्र के साथ–साथ शहरी क्षेत्र में भी आधारभूत सुविधाओं का अभाव ग्रामीण–शहरी लिंकेज के लिए एक चुनौती है। भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने शहरों की ओर व्यक्तियों के प्रवर्जन व प्रवाह को बढ़ावा दिया है जिससे शहरों में परिवहन की व्यस्तता, आवासीय सुविधाओं का अभाव, स्वच्छता की कमी जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं। अनियोजित शहरीकरण से शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ा है और शिक्षा एवं रोजगार की तलाश में आए व्यक्तियों को शहरों की वर्तमान ढांचागत सुविधाओं के तहत समायोजित करना संभव नहीं हो पा रहा है। परिणामस्वरूप शहरों में बेरोजगारी व गरीबी का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अधिक रहा है।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान में सरकार की श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन तथा स्मार्ट सिटी योजना एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे ग्रामीण–शहरी लिंकेज में अवश्य वृद्धि होगी।

ग्रामीण–शहरी लिंकेज के लिए रोजगार की उपलब्धता भारत में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता ग्रामीण–शहरी लिंकेज को बढ़ावा देती है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलें तो उनकी आय में वृद्धि होने से उनका जीवन–स्तर ऊंचा उठता है। वे कृषि उत्पादों के साथ शहरों में निर्मित माल के लिए भी मांग बढ़ाते हैं जिससे उन वस्तुओं के लिए बाजार सृजित होता है। यही नहीं अधिक आय होने पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए अपने बच्चों को शहरों में भेजते हैं, जो आगे जाकर नई तकनीक व नई पद्धतियों का ज्ञान अपने क्षेत्र के लोगों को देते हैं व ग्रामीण–शहरी लिंकेज में वृद्धि होती है। महानरेगा व सरकार द्वारा चलाई जा रही अल्प–रोजगार योजनाएं इस दिशा में कार्य कर रही हैं जो ग्रामीणों को गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराती हैं। किन्तु ग्रामीण–शहरी लिंकेज बढ़ाने हेतु ग्रामीणों द्वारा शहरी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना आवश्यक है जिसमें उनकी अशिक्षा व अकुशलता एक बड़ी चुनौती है। इस हेतु ग्रामीणों में शिक्षा के स्तर में सुधार के साथ ही कौशल विकास की आवश्यकता

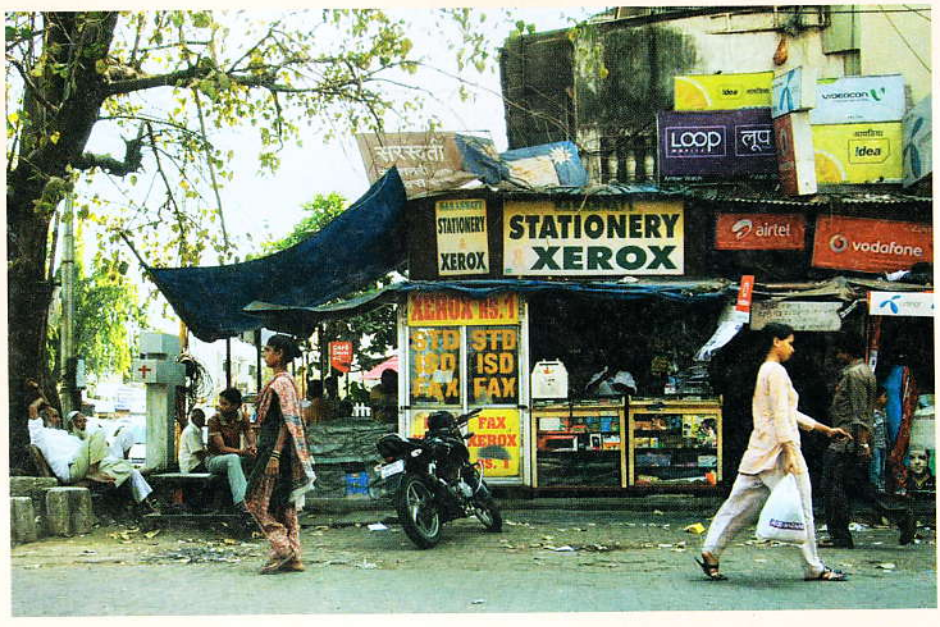

है। सरकार की "स्किल इण्डिया" योजना इस दिशा में एक पहल है।

गांवों में निजी निवेश का अभाव भी ग्रामीण–शहरी लिंकेज की एक चुनौती है। सरकारी प्रयासों से ग्रामीण कृषि भूमि व सम्पत्तियों से सम्बन्धी सूचना समय–समय पर प्रकाशित की जानी चाहिए। साथ ही ग्रामीणों को भी शहरी सम्पत्तियों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इससे ग्रामीण–शहरी लिंकेज बढ़ाया जा सकता है।

भारत में ग्रामीण–शहरी लिंकेज के अवसर

- **कृषि का विविधिकरण :** भारत में कृषि विविधिकरण की अकूत संभावनाएं मौजूद हैं। कृषि क्षेत्र में खाद्यान्नों के उत्पादन के साथ–साथ फलों, सब्जियों व नकदी फसलों के उत्पादन की संभावनाएं बढ़ाकर शहरी क्षेत्र से उद्यमियों को ग्रामीण क्षेत्र में निवेश हेतु आकर्षित करके ग्रामीण–शहरी संयोजन में वृद्धि की जा सकती है।
- **कृषि उत्पाद प्रसंस्करण उद्योग :** कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण यदि ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जाए तो इन उद्यमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। इन उद्यमों से प्राप्त उत्पादों की आपूर्ति से शहरी बाजारों का विकास होगा व क्रेता–विक्रेता के सम्पर्क से ग्रामीण क्षेत्रों का न केवल शहरी क्षेत्रों वरन् राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से भी लिंकेज बढ़ाने के अवसर भारत में उपलब्ध हैं।
- **ग्रामीण क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना :** ग्रामीण क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण युवाओं में कौशल का विकास किया जा सकता है जिससे वे शहरी क्षेत्र में प्राप्त होने वाले रोज़गारों के योग्य बन सके। साथ ही स्वयं का उद्यम शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित कर सकें। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देकर ग्रामीण–शहरी लिंकेज बढ़ाया जा सकता है।
- **परम्परागत चिकित्सा पद्धति के जानकारों व गुणीजनों का अस्तित्व :** ग्रामीण क्षेत्र में भारत की परम्परागत चिकित्सा पद्धति के जानकार व जड़ी–बूटियों से इलाज करने वाले गुणीजन उपस्थित हैं जिनके ज्ञान का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति ला सकता है व यह ग्रामीण–शहरी लिंकेज को बढ़ाने में सक्षम है।
- **जनजाति पर्यटन व पर्यावरणीय पर्यटन की संभावना :** भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कई जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी लोक परम्पराएं, लोकनृत्य, जीवनशैली पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। साथ ही गांवों के हरे–भरे पर्यावरण का लाभ लेने के लिए भी पर्यटक लालायित रहते हैं। इस तरह के पर्यटन के उद्यम के रूप में विकास से भारत में ग्रामीण–शहरी लिंकेज बढ़ाया जा सकता है।
- **रोजगार की संभावनाएं :** भारत में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। आज भी भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक (56.4 प्रतिशत) होते हुए सेवा क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत (25.3 प्रतिशत) बहुत ही कम है जिसे बढ़ाए जाने की काफी संभावनाएं हैं। गांवों में रोजगार में वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि व सम्पन्नता को बढ़ाया जा सकता है जो आधिक्य आय, बचत व निवेश को बढ़ावा देगी। यह ग्रामीण–शहरी लिंकेज का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- **पीपीपी मॉडल के माध्यम से विकास :** ग्रामीण तथा शहरी विकास क्षेत्र में भारत में निजी निवेश नहीं के बराबर है। ग्राम पंचायतों के सहयोग से यदि गांवों में तथा नगरपालिकाओं के सहयोग से नगरों में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए अर्थात सार्वजनिक–निजी सहभागिता मॉडल को अपनाया जाए तो ग्रामीण विकास के साथ–साथ ग्रामीण–शहरी लिंकेज बढ़ाया जा सकता है।

(सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग,
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर)
ई–मेल : neha_paliwal03@gmail.com